



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 19 अप्रैल, 1976

चैत्र 30, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1760/सत्रह-वि-1-47-76

लखनऊ, 19 अप्रैल, 1976

### अधिसूचना

#### विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधानमण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 पर दिनांक 16 अप्रैल, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1976)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने और कतिपय अनध्ययित घनराशि के संबंध में व्याससृजित करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

### अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) धारा 7 को 16 फरवरी, 1976 से प्रवृत्त समझा जायगा, धारा 9 ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार तदर्थ अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे, धारा 22 को 24 नवम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा और शेष धाराएँ 3 अक्टूबर, 1975 से प्रवृत्त समझी जायेंगी।

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में—

(1) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ाये जायेंगे, अर्थात्:—

“(क-1) ‘कृषि ऋण समिति’ का तात्पर्य उस ऋण समिति से है जिसके साधारण सदस्यों का बहुमत मुख्यतया कृषि कार्य करता हो;

(क-2) ‘कृषि कार्य’ के अन्तर्गत निम्नलिखित होगा:—

(i) कृषि फसलों का उत्पादन, प्रसंस्करण या क्रय-विक्रय;

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
11, 1966 की  
धारा 2 का  
संशोधन

(ii) उद्यानकरण, रेशम के कीड़े पालना या पशुपालन जिसके अन्तर्गत शूकर पालन, मत्स्य संवर्द्धन, कुक्कुट पालन और दुग्ध व्यवसाय भी है ;

(क-3) 'कृषि समिति' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है जिसके साधारण सदस्यों का बहुमत मुख्यतया कृषि कार्य करता हो ;

(क-4) 'शीर्ष समिति', 'शीर्ष स्तर समिति' या 'राज्य स्तर सहकारी समिति' का तात्पर्य निम्नलिखित से है :—

- (1) उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ ;
- (2) उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ ;
- (3) उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ ;
- (4) प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ ;
- (5) उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ ;
- (6) उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ ;
- (7) उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज फेडरेशन लिमिटेड ;
- (8) उत्तर प्रदेश केन यूनियन्स फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ ;
- (9) उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसियेशन लिमिटेड, कानपुर ; या
- (10) कोई अन्य केन्द्रीय सहकारी समिति जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है—

(i) उसकी सदस्यता में कम से कम एक ऐसी अन्य केन्द्रीय सहकारी समिति हो जिसका कारोबार या व्यापार उसी प्रकार का हो ; और

(ii) उसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में हो ; और

(iii) उसका मुख्य उद्देश्य साधारण सदस्यों के रूप में अपने से सम्बद्ध सहकारी समितियों को कार्य करने में सुविधा देना हो ;” ;

(ii) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ाया जायगा, अर्थात् :—

“(घ-1) 'केन्द्रीय समिति' या 'केन्द्रीय सहकारी समिति' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है जिसका साधारण सदस्य कोई अन्य सहकारी समिति हो और जो प्रारम्भिक सहकारी समिति न हो ;” ;

(iii) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ाया जायगा, अर्थात् :—

“(झ-1) 'ऋण समिति' का तात्पर्य उस समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिये निधि एकत्र करना हो ;” ;

(iv) खण्ड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ाया जायगा, अर्थात् :—

“(थ-1) 'प्रारम्भिक समिति' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसकी साधारण सदस्यता किसी अन्य सहकारी समिति के लिए सुलभ न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(i) किसी सहकारी क्रय-विक्रय समिति को जिसका कार्यक्षेत्र किसी जिले के एक भाग में या एक से अधिक जिले के भाग में हो, प्रारम्भिक समिति समझा जायेगा चाहे उसका साधारण सदस्य कोई अन्य समिति हो या नहीं ;

(ii) कोई प्रारम्भिक सहकारी समिति जिसका कोई अंश किसी केन्द्रीय या शीर्ष समिति ने अध्याय 6 के अधीन क्रय किया है, ऐसा अंश क्रय किये जाने पर भी पूर्ववत् प्रारम्भिक समिति ही रहेगी ;

(iii) किसी सहकारी समिति को, जिसका कार्यक्षेत्र किसी जिले का केवल एक भाग हो और जिसका मुख्य उद्देश्य बीज, रासायनिक खाद, कीट नाशक दवा, कृषि उपकरण या उपभोक्ता माल का संग्रह और अपने साधारण सदस्यों में वितरण करना हो और जिसकी सदस्यता में उसके साधारण सदस्य के रूप में कोई अन्य सहकारी समिति हो, प्रारम्भिक समिति समझा जायेगा, भले ही उसके सदस्य अन्य सहकारी समिति हों ।”

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ायी जायगी और सदेव से बढ़ायी गयी समझी जायेगी, अर्थात् :—

“(3) जहां इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन निबन्धक के सभी या कोई अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान करने के लिए उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश दिया गया हो, वहां ऐसे आदेश द्वारा उस व्यक्ति को समय-समय पर यथा संशोधित उस उपबन्ध के अधीन सभी अधिकार प्रदत्त समझा जायगा ।”

4—मूल अधिनियम की धारा 15 में—

धारा 15 का संशोधन

(i) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी, अर्थात्:—

“(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या किसी समिति की किसी उप-विधि के होते हुए भी, उपधारा (1) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी बैठक की नोटिस सम्बद्ध समितियों के सदस्यों को दी जायेगी, और प्रारम्भिक संकल्प की प्रतियां ऐसी समितियों के सदस्यों और ऋणदाताओं पर निम्नलिखित किसी एक या अधिक रीति से तामील की जायेगी, अर्थात् :—

(क) लिखित अभिस्वीकृति प्राप्त करके व्यक्तिगत तामील द्वारा; या

(ख) जिस व्यक्ति ने खण्ड (क) के अधीन लिखित रूप में प्राप्ति अभिस्वीकार की हो उसका अपवाद करके, प्रत्येक व्यक्ति के पते पर, जैसा समिति के अभिलेख में उल्लिखित हो, प्रेषण प्रमाण-पत्र के अधीन डाक द्वारा, और किसी ऐसे समाचार-पत्र में, जिसका समिति के कार्य क्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशन द्वारा भी।”;

(ii) उपधारा (3) में, खण्ड (i) में, शब्द “प्रारम्भिक संकल्प की एक प्रति उसे प्राप्त होने से तीन मास की अवधि के भीतर” के स्थान पर शब्द “उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर” रखे जायेंगे;

(iii) उपधारा (4) में, शब्द “समस्त समितियों के सभी सदस्यों तथा ऋणदाताओं को प्रारम्भिक संकल्प प्राप्त होने के तीन मास” के स्थान पर शब्द “उपधारा (3) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट अवधि के” रखे जायेंगे।

5—मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

धारा 16 का संशोधन

(i) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

“(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या ऐसी समिति की किसी उप-विधि के होते हुए भी, इस धारा में निर्दिष्ट किसी बैठक की नोटिस समिति के सदस्यों को दी जायेगी और प्रारम्भिक संकल्प की एक प्रति समिति के सदस्यों और ऋणदाताओं पर धारा 15 की उपधारा (2) में, जो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी, विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक रीति से तामील की जायेगी।”;

(ii) उपधारा (3) में, खण्ड (i) में शब्द “प्रारम्भिक संकल्प उसे प्राप्त होने से, तीन मास की अवधि के भीतर” के स्थान पर शब्द “धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन जैसा कि वह इस धारा की उपधारा (2) के आधार पर लागू किया जाय, प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से, या यथास्थिति, उसके खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर” रखे जायेंगे;

(iii) उपधारा (4) में, शब्द “समिति के समस्त सदस्यों और ऋणदाताओं को प्रारम्भिक संकल्प प्राप्त होने से तीन मास” के स्थान पर शब्द, “उपधारा (3) के खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट अवधि के” रखे जायेंगे।

6—मूल अधिनियम की धारा 20 में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में खण्ड (क) के पश्चात् निम्न-लिखित खण्ड बढ़ाया जायगा, अर्थात् :—

धारा 20 का संशोधन

“(कक) किसी सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा, यदि—

(i) वह बाकीदार है और कम से कम छः मास की अवधिपर्यन्त बाकीदार रहा है; या

(ii) यह ऐसी बाकीदार समिति का, जैसा कि उप खण्ड (i) में निर्दिष्ट है, प्रतिनिधि है।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ शब्द “बाकीदार” का तात्पर्य—(i) ऐसे सदस्य से है (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या निगमित निकाय हो) जिसने संबद्ध समिति के किसी देय का भुगतान देय दिनांक को न किया हो; या

(ii) ऐसे सदस्य सहकारी समिति से है जिसने देय दिनांक को कुल देयों के फम से कम 75 प्रतिशत का भुगतान न किया हो।”

धारा 29. का  
संशोधन

## 7—मूल अधिनियम की धारा 29 में—

(i) उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "जब तक कि उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन नये निर्वाचन न हो जायें अथवा उपधारा (5) के अधीन निबन्धक द्वारा नाम निर्देशन न कर दिये जायें" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा, अर्थात् :—

"जब तक कि इस धारा के अधीन समिति द्वारा नये निर्वाचन न किये जायें या निबन्धक द्वारा अन्य व्यवस्था न की जाय" ;

(ii) उपधारा (3), (4), (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराये रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"(3) प्रबन्ध कमेटी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व धारा 32 के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक में प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिये कार्यवाही करे, और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उन सदस्यों का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल उपधारा (2) के अधीन समाप्त होता है।

(4) यदि समिति, वहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल रहती है तो जब तक कि समिति के सदस्यों का निर्वाचन न हो जाये, तब तक के लिये निबन्धक समिति के कार्यकालाप के प्रबन्ध के लिये—

(i) किसी शीर्ष या केन्द्रीय समिति की स्थिति में, प्रशासक नियुक्त करेगा, और

(ii) किसी अन्य समिति की स्थिति में, प्रशासक नियुक्त कर सकता है, और उसे ऐसी व्यवस्था में समय-समय पर परिवर्तन करने का अधिकार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक इस उपधारा के अधीन किसी शीर्ष या केन्द्रीय समिति में कोई प्रशासक नियुक्त नहीं किया जाये, तब तक समिति का सचिव चार सप्ताह से अनधिक अवधि के लिये प्रबन्ध कमेटी के केवल वर्तमान कर्तव्यों का प्रभार ग्रहण करेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन निबन्धक द्वारा नियुक्त प्रशासक को, ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुये, जिन्हें निबन्धक समय-समय पर दे सकता है, प्रबन्ध कमेटी के या समिति के किसी अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने का अधिकार होगा और इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के सभी प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह प्रबन्ध कमेटी है।

(6) उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्रशासक, अपनी नियुक्ति के दिनांक से या उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के दिनांक से पांच मास के भीतर जो भी पश्चातवर्ती हो, इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार समिति का प्रबन्ध उससे ग्रहण करने के लिये, प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उस अवधि को जिसमें प्रशासक को विधि न्यायालय के किसी आदेश से ऐसा करने से रोका जायें, पांच मास की उक्त अवधि की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(7) जहाँ प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल 3 अक्तूबर, 1975 के (जिसे आगे इस धारा में 'उक्त दिनांक' कहा गया है) पूर्व समाप्त हो गया हो, वहाँ इस बात के होते हुये भी कि निबन्धक ने उपधारा (4) के अधीन, जैसा कि वह उक्त दिनांक के ठीक पहले था, कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी, निबन्धक उक्त दिनांक के पश्चात् यथाशीघ्र उपधारा (4) के अनुसार, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, कार्यवाही करेगा, और तदन्तर उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड के आधार पर, जैसा कि वह उक्त दिनांक के पहले था, या धारा 35 के अधीन किसी आदेश के आधार पर, पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने पद से तत्काल मुक्त समझा जायेगा और उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा प्रतिस्थापित उपधारा (4) के अधीन निबन्धक द्वारा नियुक्त प्रशासक ही समिति की प्रबन्ध कमेटी तथा अधिकारियों के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये सक्षम होगा।"

8—मूल अधिनियम की धारा 31 में—

(क) उपधारा (1) में शब्द "प्रत्येक सहकारी समिति का एक सचिव होगा" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 31-क में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक सहकारी समिति का एक सचिव होगा" रख दिये जायेंगे, और शब्द और अंक "धारा 121 और 122" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 121, 122 और 122-क" रखे जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द और अंक "धारा 121 या 122" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 121, धारा 122 या धारा 122-क" रखे जायेंगे।

धारा 31 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, अर्थात्:—

नयी धारा 31-क का बढ़ाया जाना

"31-क—(1) प्रत्येक शीर्ष समिति के लिये, सचिव के स्थान पर एक प्रबन्ध-निदेशक शीर्ष समितियों के होगा जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रथम वर्ग के अधिलेखित सचिव के स्थानकारी से अनिम्न पद का सरकारी सेवक होगा, और उसकी सेवायें पर प्रबन्ध-निदेशक समिति में प्रतिनियुक्ति पर सम्भली जायेंगी और उसे राज्य सरकार की नियुक्ति द्वारा अवधारित वेतन और भत्ता समिति के निधि से दिया जायगा।

(2) प्रबन्ध-निदेशक प्रबन्ध कमेटी का पदेन सदस्य होगा।

(3) किसी शीर्ष समिति के सम्बन्ध में, अधिनियम में सचिव के प्रति समस्त निर्देश, जहाँ कहीं व्यवहार्य हो, प्रबन्ध-निदेशक के प्रति निर्देश समझा जायगा।

(4) प्रबन्ध निदेशक शीर्ष समिति का मुख्य-कार्यपालक अधिकारी होगा और प्रबन्ध कमेटी और सभापति के ऐसे नियंत्रण में रहते हुए, जैसा नियमों और समिति की उपविधियों में उपबन्धित किया जाये, उसका निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा, अर्थात्:—

(i) समिति के प्रशासन पर सामान्य नियंत्रण रखना;

(ii) प्रबन्ध कमेटी और सामान्य निकाय की बैठक बुलाना;

(iii) समिति की ओर से समस्त धन और प्रतिभूति प्राप्त करना और समिति की रोकड़ बाकी और अन्य सम्पत्तियों के समुचित अनुरक्षण और अभिरक्षा का प्रबन्ध करना;

(iv) बचन-पत्रों, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों को पृष्ठांकित और संक्रमित करना और समिति की ओर से चेक और अन्य परक्राम्य संलेख का पृष्ठांकन, हस्ताक्षर और परक्रमण करना;

(v) समिति के दिनानुदिन कार्य और मामलों के सामान्य संचालन, पर्यवेक्षण और प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होना;

(vi) समस्त जमा रसीदों पर हस्ताक्षर करना और बैंक में समिति का लेखा चलाना;

(vii) समिति के पक्ष में समस्त बन्ध-पत्रों और अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करना;

(viii) समिति के बजट प्राविधानों के अधीन रहते हुए तीन मास की अवधि के लिये तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन करना और नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में बोर्ड के माध्यम से उन पर भर्ती करना जैसा कि धारा 122 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों में व्यवस्थित है;

(ix) समिति के कर्मचारियों के अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व अवधारित करना;

(x) समिति द्वारा या उसके विरुद्ध या अन्यथा समिति के मामलों के सम्बन्ध में कोई दावा या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित, संचालित, प्रतिवादित, प्रशमित या परित्यक्त करना और समिति द्वारा या उसके विरुद्ध किसी दावा या मांग का प्रशमन करना और भुगतान या तुष्टि के लिये समय देना;

(xi) ऐसे विनियमों के, यदि कोई हों, जिन्हें प्रबन्ध कमेटी बनाये, अधीन रहते हुए, बातचीत करना और निर्माण-कार्य के दौरान 5 लाख रुपये तक की प्रत्येक और उसके पश्चात् 2½ लाख रुपये तक की प्रत्येक संविदा को स्वीकृत करना और समिति के प्रयोजनार्थ, उपर्युक्त किसी विषय के सम्बन्ध में समिति के नाम से और उसकी ओर से ऐसे समस्त कार्य, कृत्य और बात करना;

(xii) अपना अन्तिम नियंत्रण और प्राधिकार रखते हुए, किसी समिति के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को अपने में निहित सभी या किसी अधिकार, प्राधिकार और विवेकाधिकार प्रत्यापोजित करना।”

धारा 34 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ायी जायगी, अर्थात् :—

“(7-क)—इस अधिनियम में या किसी समिति की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी—

(i) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा या उपधारा (7) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कोई सरकारी सेवक या तो नाम से या शासकीय पदनाम से नाम-निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(ii) शासकीय पदनाम से इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट कोई सरकारी सेवक प्रबन्ध कमेटी की किसी विशिष्ट बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है, और ऐसे अधिकारी को कमेटी के विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकार होगा।”

नयी धारा 35-क का बढ़ाया जाना

11—मूल अधिनियम की धारा 35 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, अर्थात् :—

“35-क (1)—इस अध्याय के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां दो लगातार सहकारी वर्षों के लिए (जिसके अन्तर्गत इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व की कोई अवधि भी है)—

(क) किसी प्रारम्भिक समिति का, जो ऋण समिति है, किसी सहकारी वर्ष में अपने सदस्यों के विरुद्ध कुल देयों का सत्तर प्रतिशत से अधिक ऐसे वर्ष के अन्त में अदत्त रह जाय, या

(ख) किसी ऐसे वर्ष के अन्त में बाकीदार सदस्यों की संख्या ऐसी समिति के ऋणी सदस्यों की कुल संख्या के सत्तर प्रतिशत से अधिक हो जाय,

वहां किसी ऐसी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सभापति और सभी सदस्य उपधारा (3) के अधीन आदेश प्रभावी होने पर इस रूप में अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे।  
(2) उपधारा (1) के उपबन्ध, जिस प्रकार वे किसी प्रारम्भिक ऋण समिति पर लागू होते हैं, वित्त पोषण बैंक पर, आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानों “सत्तर प्रतिशत” के निर्देश को “साठ प्रतिशत” के निर्देश द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

(3) किसी समिति या बैंक के सम्बन्ध में, जैसा कि उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, निबन्धक ऐसी समिति या बैंक के, जिसे वह उपयुक्त समझे, कार्यों के प्रबन्ध के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसे वह उचित समझे और धारा 35 की उपधारा (3), (4), (5) और (6) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

धारा 44 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 44 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) में, शब्द और कोष्ठक (“जिसे इस अध्याय में आगे ‘शीर्ष समिति’ कहा गया है”) निकाल दिये जायेंगे।

धारा 45 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 45 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) में, शब्द और कोष्ठक (“जिसे आगे इसे अध्याय में ‘केन्द्रीय समिति’ कहा गया है”) निकाल दिये जायेंगे।

नयी धारा 71-क का बढ़ाया जाना

14—मूल अधिनियम के अध्याय 9 में, धारा 71 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, अर्थात् :—

“71-क (1)—यदि कोई सहकारी समिति (जिसे आगे इस धारा में ऋणी समिति कहा गया है) अपने ऋण का भुगतान किसी अन्य सहकारी समिति को (जिसे का ऋणी समिति आगे इस धारा में ऋणदाता समिति कहा गया है) इस कारण करने में असमर्थ है कि उसके सदस्यों ने धन का भुगतान करने में चूक किया है और क विरुद्ध अधिकार ऋणी समिति की प्रबन्ध कमेटी ने अपने सदस्यों से प्राप्य धन की वसूली के लिये आवश्यक कार्यवाही करने में लोप या उपेक्षा बरती है तो इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऋणदाता समिति लिखित नोटिस द्वारा उक्त कमेटी को चूक करने वाले सदस्यों के विरुद्ध धारा 70 या, यथास्थिति, धारा 92 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दे सकती है।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस का अनुपालन उस नोटिस की तारीख के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर ऋणी समिति की प्रबन्ध कमेटी नहीं करती है, तो चूक करने वाले ऐसे सदस्यों के विरुद्ध ऋणदाता समिति स्वयं धारा 70 या, यथास्थिति, धारा 92 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकती है मानों वह ऋणदाता समिति के सदस्य हों और उस दशा में इस अधिनियम और इसके अधीन बने नियम और ऋणी समिति की उप विधियों के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों उक्त उपबन्धों में ऋणी समिति और उसकी प्रबन्ध कमेटी और अधिकारियों के प्रति निर्देश ऋणदाता समिति और उसके प्रबन्ध कमेटी और अधिकारियों के प्रति निर्देश हों।

(3) जहां ऋणदाता समिति ने ऋणी समिति द्वारा देय किसी धन के सम्बन्ध में ऋणी समिति के विरुद्ध धारा 92 में निर्दिष्ट अभिनिर्णय या आदेश प्राप्त कर लिया है, वहां ऋणदाता समिति इस अधिनियम के और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार या तो ऋणी समिति की परिसम्पत्तियों से, या उसके सदस्यों से ऋणी समिति को उनसे प्राप्य ऋण की मात्रा तक, या दोनों से ऐसे धन की वसूली के लिये कार्यवाही कर सकती है।”

15—मूल अधिनियम की धारा 95 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायेगी, अर्थात् :—

नयी धारा 95-क  
का बढ़ाया जाना

“95-क (1)—निबन्धक, धारा 34 में निर्दिष्ट समिति या कृषि ऋण समिति द्वारा किसी सदस्य को दिये गये किसी ऋण या उसकी किसी किस्त की बकाया कृषि समिति के की वसूली के लिये प्रार्थना-पत्र देने पर और ऐसे ऋण के सम्बन्ध में लेखा देयों की वसूली के विवरण प्रस्तुत करने पर और ऐसी जांच, यदि कोई हो, जिसे वह उचित लिये विशेष समझे, करने के पश्चात् देय धनराशि की वसूली के लिये प्रमाण-पत्र उपबन्ध जारी कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन निबन्धक द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र अन्तिम और देयों का निश्चायक सबूत होगा, जिसे मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा।”

16—मूल अधिनियम की धारा 103 में, उपधारा (2) में—

धारा 103 का  
संशोधन

(i) खण्ड (क) में श्रंक “6” निकाल दिया जायगा;

(ii) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जायेंगे, अर्थात् :—

“(ख) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के खण्ड (2), खण्ड (3) या खण्ड (6) के अधीन अपराध करता है, दोषसिद्धि पर किसी प्रकार के कारावास के दण्ड का भागी होगा जो दो वर्ष तक हो सकता है और अर्थ दण्ड का भी भागी होगा जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है ;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा।”

17—मूल अधिनियम की धारा 117 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायेगी, अर्थात् :—

नयी धारा 117-क  
का बढ़ाया जाना

“117—क—धारा 29, धारा 34, धारा 35 या धारा 35-क के अधीन निबन्धक या राज्य सरकार के द्वारा जो आदेश दिया जाय या दिया जाना भावित हो कतिपय मामलों उसको विरुद्ध समिति या किसी अधिकारी या उसकी प्रबन्ध कमेटी द्वारा में मुकदमों पर किसी न्यायालय में दायर की गयी या संस्थित किन्हीं कार्यवाहियों का होने वाले व्यय खर्च देने के प्रयोजनार्थ समिति की निधि से कोई व्यय निबन्धक की का नियंत्रण लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा।”

18—मूल अधिनियम की धारा 122 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायेगी, अर्थात् :—

नयी धारा 122-क  
का बढ़ाया जाना

“122-क (1)—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार ऐसी सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के ऐसे कर्मचारियों कतिपय सेवाओं की, जिसे राज्य सरकार उचित समझे, ऐसी सहकारी समितियों के का केन्द्रीयकरण लिये सर्वसामान्य एक या अधिक सेवाओं के सृजन के लिये उपबन्ध नियमों द्वारा कर सकती है और किसी ऐसी सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती की प्रणाली और सेवा की शर्तों को नियत कर सकती है।

(2) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय तब ऐसी सेवा में सम्मिलित पदों के कर्मचारी यदि उपयुक्त पाये जाएं, अस्थायी रूप से या अन्तिम रूप से सेवा में आमेिलित किये जायेंगे, जब तक कि कोई ऐसा कर्मचारी नियत अवधि के भीतर नियत प्राधिकारी को उस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा ऐसी सेवा का सदस्य न होने के अपने विकल्प की सूचना न दे दे और अन्य कर्मचारियों की सेवाएं नियत रीति से समाप्त हो जायेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई कर्मचारी उपर्युक्त नोटिस देता है वहां समिति में उसकी सेवाएँ ऐसी नोटिस के दिनांक से समाप्त हो जायेंगी और वह समिति से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो—

(क) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, उसकी सेवा के तीन मास की अवधि के या सेवा की शेष अवधि के, जो भी कम हो, उसके वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ता भी है) के बराबर होगा ;

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में, उसकी सेवा के एक मास के या सेवा की शेष अवधि के, जो भी कम हो, उसके वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ता भी है) के बराबर होगा :

अथवा प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी ऐसे व्यक्ति का उक्त सेवा में सम्मिलित पद से भिन्न किसी पद पर स्वत्व (लीएन) हो, वहां वह उस पद पर, जिस पर उसका स्वत्व है, प्रतिवर्तित किये जाने का हकदार होगा और यदि वह इस प्रकार प्रतिवर्तित होता है तो वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा ।”

धारा 125 का  
संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 125 में,—

(क) उपधारा (2) में, शब्द “सम्बद्ध समितियों को सुनवाई का एक और अवसर देने के पश्चात्” निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द “सभी समितियों के समस्त सदस्यों और ऋणदाताओं द्वारा उपधारा (3) में अभिविष्ट प्रारम्भिक संकल्प की प्राप्ति से तीन मास” के स्थान पर शब्द “धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्राप्ति होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन” रखे जाएंगे ।

धारा 126 का  
संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 126 में,—

(क) उपधारा (2) में, शब्द “सम्बद्ध समिति को सुनवाई का एक और अवसर देने के पश्चात्” निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द “समिति के सभी सदस्यों तथा ऋणदाताओं द्वारा उपधारा (3) में अभिविष्ट प्रारम्भिक संकल्प की प्राप्ति से तीन मास” के स्थान पर शब्द “धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्राप्ति होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन” रखे जायेंगे ।

कतिपय अनर्थायित  
निक्षेप का संस्थान  
को अन्तरण

21—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संविदा या लिखत में किसी बात के होते हुए भी, य 0 पी 0 कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में (जिसे यहां आगे बैंक कहा गया है) उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की ओर से राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 3072-एस (2)/12-सी-188-1948, दिनांक 24 नवम्बर, 1948 और संख्या 3321-एस/12-सी-188-1948, दिनांक 19 जनवरी, 1949 के अनुसरण में सावधि निक्षेप के रूप में जमा की गयी समस्त धनराशि, उस पर व्याज सहित, जो 24 नवम्बर, 1975 को संबद्ध गन्ना उत्पादकों द्वारा अर्थायित न हो, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान को (जिसे आगे संस्थान कहा गया है) ऐसी अवधि के भीतर, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेशित करे, बैंक द्वारा दी जायगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अन्तरित की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में बैंक और संस्थान के मध्य कोई विवाद राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायगा, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा और उससे दोनों बाध्य होंगे ।

(3) संस्थान इस प्रकार प्राप्त धनराशि को एक पृथक् लेखा में रखेगा, और उसको, यथास्थिति, जमाकर्ताओं या उनके विधिक प्रतिनिधियों की ओर से न्यास के रूप में रखेगा ।

(4) बैंक द्वारा संस्थान को उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने पर, बैंक केवल इस प्रकार भुगतान की गयी राशि की सीमा तक अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायगा, और जमाकर्ताओं या उनके विधिक प्रतिनिधियों को उसका भुगतान करने का दायित्व उपर्युक्त सीमा तक संस्थान को अन्तरित हो जायगा ।



(5) उपधारा (1) के अधीन संस्थान को भुगतान होने पर यथाशीघ्र, संस्थान एक सामान्य नोटिस, जिसमें ऐसे सभी विवरण होंगे, उस रीति से, जिसका निदेश राज्य सरकार आदेश द्वारा दे, प्रकाशित करेगा कि संस्थान को इस प्रकार अन्तरित धनराशि में से उनको देय भुगतान के लिये यथा-स्थिति, जमाकर्ताओं या उनके विधिक प्रतिनिधियों के दाव (जो नोटिस के प्रकाशन के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत किये जायेंगे) ग्रामंजित किये जाते हैं।

(6) सामान्य नोटिस के अनुसरण में प्राप्त कोई दावा गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी ऐसे अधिकारी द्वारा (जिसे आगे अध्यक्षता प्राधिकारी कहा गया है) जो सहायक गन्ना आयुक्त से निम्न श्रेणी का न हो, विनिश्चित किया जायेगा।

(7) यदि उपधारा (6) के अधीन अध्यक्षता प्राधिकारी द्वारा कोई दावा अस्वीकार कर दिया जाय, तो अध्यक्ष को उस जिले के, जिसमें जमाकर्ता गन्ना उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य था, जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।

(8) उपधारा (6) के अधीन अध्यक्षता प्राधिकारी का विनिश्चय, उपधारा (7) के अधीन किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा, और ऐसी अपील में, यदि कोई हो, जिला न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा।

(9) संस्थान को अन्तरित की गयी राशि में से, कोई राशि, जिसके लिये सामान्य नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई दावा न किया गया हो, या जिसके संबंध में उपर्युक्त प्रकार से प्रस्तुत दावा को अंतिम रूप से अस्वीकार कर दिया गया हो, परित्यक्त सम्पत्ति समझी जायगी और स्वामी-हीन रिवय के रूप में राज्य में निहित हो जायगी और वह ऐसी निधि में, जिसे उत्तर प्रदेश गन्ना विकास निधि कहा जायगा, अन्तरित हो जायगी और उत्पन्न भाग समझी जायगी।

(10) गन्ना की खेती के विकास, अनुसंधान और प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिये और गन्ना उत्पादकों के लिये सामान्य उपयोगिता के ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये, जैसा गन्ना आयुक्त समय-समय पर निदेश दे, वह निधि संस्थान में निहित होगी और उसके द्वारा रखी और प्रशासित की जायगी।

22--(1) उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, 1976 एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

निरस्त और  
अपवाद]

(2) ऐसे निरस्त और उपधारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1975, और उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों का उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में निक्षेप (अनध्ययित निक्षेप के लिये न्यास) अध्यादेश, 1975 के निरस्त के होते हुए भी, कोई कार्य या कोई कार्यवाही, जो

(क) उक्त उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1975 द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया हो या की गयी हो, उसे इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस प्रकार संशोधित मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन किसी समिति के प्रशासन के लिए कोई तदर्थ कमेटी नियुक्त द्वारा नियुक्त की गयी थी, वहां वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो सप्ताह के भीतर तदर्थ कमेटी के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करेगा और जब तक ऐसा प्रशासक नियुक्त न किया जाय तब तक प्रबन्ध कमेटी के केवल वर्तमान कर्तव्यों का प्रभार तदर्थ कमेटी ग्रहण करेगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी शीर्ष या केंद्रीय समिति से भिन्न किसी समिति के संबंध में जहां नियन्त्रक ने प्रशासक नियुक्त किया है, वहां वह यदि उचित समझे, वहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी को समिति का प्रबन्ध पुनः सौंप सकता है, किन्तु इससे उक्त उप-धारा (4) के अधीन पुनः कार्य करने के लिये, जब कभी वह ऐसा करना उचित समझे, उसके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ; या

(ख) उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों का उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में निक्षेप (अनध्ययित निक्षेप के लिए न्यास) अध्यादेश, 1975 के अधीन किया गया हो या की गयी हो, उसे इस अधिनियम की धारा 22 के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी,

मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

No. 1760 (2) /XVII-V-1-47-76

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the overnor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Vidhi (Sanshodhan Aur Prakirna Upbandh) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 1976), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 16, 1976 :

**THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE LAWS (AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1976**

(U. P. ACT NO. 12 OF 1976)

*[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 and to provide for the creation of a trust in respect of certain unclaimed sums of money and for matters connected therewith.*

It is HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India, as follows :

Short title and  
commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1976.

(2) Section 7 shall be deemed to have come into force on February 16, 1976, section 9 shall come into force on such date as the State Government may by notification, appoint in that behalf, section 22 shall be deemed to have come into force on November 24, 1975 and rest of the sections shall be deemed to have come into force on October 3, 1975.

Amendment of  
section 2 of U.P.  
Act 11 of 1966.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act—

(i) after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely :—

“(a-1) ‘agricultural credit society’ means a credit society majority of the ordinary members whereof are primarily engaged in agricultural occupation ;

(a-2) ‘agricultural occupation’ shall include—

(i) production, processing or marketing of agricultural crops ;

(ii) horticulture, sericulture or animal husbandry which includes piggery, pisciculture, poultry farming and dairying ;

(a-3) ‘agricultural society’ means a co-operative society the majority of the ordinary members whereof are primarily engaged in agricultural occupation ;

(a-4) ‘apex society’, ‘apex level society’ or ‘state level co-operative society’ means—

(1) U. P. State Co-operative Land Development Bank Ltd. Lucknow ;

(2) U. P. Co-operative Bank Ltd., Lucknow ;

(3) U. P. Co-operative Federation Ltd., Lucknow ;

- (4) Pradeshik Co-operative Dairy Federation Ltd., Lucknow;
- (5) U. P. Co-operative Union Ltd., Lucknow;
- (6) U. P. Upbhokta Sahkari Sangh Ltd., Lucknow;
- (7) U. P. Co-operative Sugar Factories Federation Ltd.;
- (8) U. P. Cane Unions Federation Ltd., Lucknow;
- (9) U. P. Industrial Co-operative Association Ltd., Kanpur;

or

(10) any other central co-operative society fulfilling the following conditions :—

(i) it includes in its membership at least one other central co-operative society in the same line of business or trade; and

(ii) its area of operation covers the whole of Uttar Pradesh; and

(iii) its primary object is to facilitate the operation of the co-operative societies affiliated to it as ordinary members;”;

(ii) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely :—

“(d-1) ‘central society’ or central co-operative society means a co-operative society, which has any other co-operative society as its ordinary member and is not a primary co-operative society;”;

(iii) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely :—

“(i-1) ‘credit society’ means a society which has as its primary object the raising of funds to be lent to its members;”;

(iv) after clause (q), the following clause shall be inserted, namely :—

“(q-1) ‘primary society’ means a co-operative society ordinary membership whereof is not open to any other co-operative society :

Provided that—

(i) a co-operative marketing society, the area of operation whereof is only a part of a district or part of more than one district shall be deemed to be a primary society whether or not any other co-operative society is its ordinary members;

(ii) a primary co-operative society any share whereof has been purchased under Chapter VI, by a central or apex society shall continue to be a primary society notwithstanding the purchase of such shares;

(iii) a co-operative society, the area of operation whereof is only a part of a district and the primary object whereof is to arrange for the storage and distribution of seeds, fertilizers, pesticides, agricultural appliances or consumers goods to its ordinary members and the membership whereof includes any other co-operative society as its ordinary member, shall be deemed to be primary society notwithstanding the membership of other co-operative society in it;”.

Amendment  
section 3.

3. In section 3 of the principal Act, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely :—

"(3) Where any order has been made under sub-section (2) conferring on any person all or any of the powers of the Registrar under any provision of this Act, such order shall be deemed to confer on him all the powers under that provision as may be amended from time to time."

Amendment of  
section 15.

4. In section 15 of the principal Act—

(i) for sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(2) Notwithstanding any other provision of this Act or of any bye-law of any society, notices of any meeting referred to in sub-section (1) or sub-section (4) shall be given to the members of the societies concerned, and copies of the preliminary resolution shall be served on the members and creditors of such societies in any one or more of the following manners, namely :—

(a) by delivery in person under acknowledgement in writing,  
or

(b) except in respect of any person who has acknowledged receipt in writing under clause (a), by post under certificate of posting at the address of each such person as noted in the society's records, and also by publication in a newspaper having circulation in the area of operation of the society."

(ii) in sub-section (3), in clause (i), for the words "within a period of three months from his receipt of the copy of the preliminary resolution", the words "within a period of thirty days from the date of receipt of the copy of the preliminary resolution under clause (a) of sub-section (2) or, as the case may be, from the date of its publication in a newspaper under clause (b) of that sub-section" shall be *substituted*;

(iii) in sub-section (4), for the words "three months from the receipt of the preliminary resolution by all the members and creditors of all societies", the words "the period referred to in clause (i) of sub-section (3)" shall be *substituted*.

Amendment of  
section 16.

5. In section 16 of the principal Act—

(i) for sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(2) Notwithstanding any other provision of this Act or of any bye-law of such society, notices of any meeting referred to in this section shall be given to the members of the society and a copy of the preliminary resolution shall be served on the members and creditors of the society in any one or more of the manners specified in sub-section (2) of section 15, which shall *mutatis mutandis* apply."

(ii) in sub-section (3), in clause (i), for the words "within a period of three months from the receipt of the preliminary resolution", the words "within a period of thirty days from the date of receipt of a copy of the preliminary resolution under clause (a) of sub-section (2) of section 15 as applicable by virtue of sub-section (2) of this section, or, as the case may be, from the date of its publication in a newspaper under clause (b) thereof" shall be *substituted*;

(iii) in sub-section (4), for the words "three months from the receipt of the preliminary resolution by all the members and creditors of the society", the words "the period referred to in clause (i) of sub-section (3)" shall be *substituted*.

Amendment of  
section 20.

6. In section 20 of the principal Act, in the proviso, *after* clause (a) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(aa) a member shall have no right of vote if—

(i) he is defaulter and has been a defaulter for a period of not less than six months; or

(ii) he is a delegate of a society which is such defaulter as is referred to in sub-clause (i).

*Explanation* :—For the purposes of this clause, the word “defaulter” means :—

- (i) a member (whether individual or body corporate) who has failed to pay any dues of the society concerned on the due date ; or
- (ii) a member co-operative society which has failed to pay not less than 75 per cent of the total dues on the due date.”

7. In section 29 of the principal Act—

Amendment of section 29.

(i) in the proviso to sub-section (2), for the words “till fresh elections are held by the society under sub-section (3) or sub-section (4) or nominations are made by the Registrar under sub-section (5)”, the following shall be substituted, namely :—

“until fresh elections are held by the society or other arrangements are made by the Registrar under this section” ;

(ii) for sub-sections (3), (4), (5) and (6), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

“(3) It shall be the duty of the Committee of Management to take steps before the expiry of its term for election of members of the Committee of Management as provided in section 32 at an annual general meeting, and the members so elected shall replace the members whose term expires under sub-section (2).

(4) If the society fails to elect the members of Committee of Management before the expiry of the term of the outgoing committee of management, the Registrar—

(i) in the case of an apex or a central society, shall appoint an Administrator, and

(ii) in the case of any other society, may appoint an Administrator,

for the management of the affairs of the society until the election of the members of the Committee of Management is held, and he shall have power to make any change in such arrangement from time to time :

Provided that for so long as no Administrator is appointed in an apex or a central society under this sub-section, the Secretary of the society shall be in charge only of the current duties of the Committee of Management for a period not exceeding four weeks.

(5) The Administrator appointed by the Registrar under sub-section (4) shall, subject to any directions which the Registrar may from time to time give, have the power to perform all or any of the functions of the Committee of Management or of any officer of the society and shall be deemed for all purposes under this Act, the rules and the bye-laws of the society to be the Committee of Management.

(6) The Administrator appointed under sub-section (4) shall, within a period of five months from the date of his appointment or from the commencement of the Uttar Pradesh Co-operative Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1976, whichever is later, arrange for the reconstitution of the Committee of Management in accordance with this Act, the rules and the byelaws of the society to take over the management of the society from him :

Provided that any period during which the Administrator is restrained from so acting by an order of a court of law, shall be excluded in computing the said period of five months.

(7) Where the term of a Committee of Management has expired before the third day of October, 1975 (hereinafter, in this section, referred to as the said date), then notwithstanding that action had been initiated by the Registrar under sub-section (4) as it stood immediately before the said date, the Registrar shall as soon as may be after the said date take action in accordance with sub-section (4), as amended by the Uttar Pradesh Co-operative Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1976 and thereupon every person holding office either by virtue of the proviso to sub-section (2) as it stood before the said date or by virtue of any order under section 35, shall be deemed to have ceased to hold such office forthwith and the Administrator appointed by the Registrar under

sub-section (4) as substituted by the Uttar Pradesh Co-operative Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1976, shall alone be competent to exercise the powers of the Committee of Management and of officers of the society."

Amendment of section 31.

8. In section 31 of the principal Act—

(a) in sub-section (1) for the words "There shall be a Secretary of every co-operative society", the words and figures "Save as provided in section 31-A, there shall be a secretary of every Co-operative Society", shall be substituted, and for the words and figures "sections 121 and 122" the words, figures and letter, "sections 121, 122 and 122-A" shall be substituted;

(b) in sub-section (3), for the words and figures "section 121 or section 122" the words, figures and letter "section 121, section 122 or section 122-A" shall be substituted.

Insertion of new section 31-A.

9. After section 31 in the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"31-A. (1) For every apex society there shall be, instead of a Secretary, Appointment of a Managing Director who shall be a Government servant Managing Director not below the rank of a class I Officer, nominated by Secretary for the State Government, and his services shall be deemed Apex Societies. to be on deputation with the society and his salary and allowances, as determined by the State Government, shall be paid from the funds of the society.

(2) The Managing Director shall be *ex officio* member of the Committee of Management.

(3) All references in the Act to Secretary shall in relation to an apex society be construed, wherever practicable, as references to the Managing Director.

(4) The Managing Director shall be the Chief Executive Officer of the apex society and subject to such control of the Committee of Management and the Chairman, as may be provided in the rules and the byelaws of the society he shall have the following duties and responsibilities, namely:—

(i) to have general control over the administration of the society;

(ii) to convene meetings of the Committee of Management and the general body;

(iii) to receive all moneys and securities on behalf of the society and to make arrangements for the proper maintenance and custody of cash balances and other properties of the society;

(iv) to endorse and transfer promissory notes, Government and other securities and to endorse, sign and negotiate cheques and other negotiable instruments on behalf of the society;

(v) to be responsible for the general conduct, supervision and management of the day-to-day business and affairs of the society;

(vi) to sign all deposit receipts and operate the accounts of the society with banks;

(vii) to sign all bonds and agreements in favour of the society;

(viii) to create, subject to provisions contained in the budget of the society, class III and class IV posts for a period of 3 months and to make, as appointing authority, recruitment thereto through the Board as provided in the regulations framed by the State Government in exercise of the powers under sub-section (2) of section 122;

(ix) to determine the powers, duties and responsibilities of the employees of the society;

(x) to institute, conduct, defend, compound or abandon any suit or other legal proceeding by or against the society or otherwise concerning the affairs of the society and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any claims or demand by or against the society;

(xi) subject to the regulations, if any, which may be framed by the Committee of Management to enter into negotiations and sanction contracts up to the value of Rs.5 lakhs each during the construction phase and up to Rs.2½ lakhs each thereafter and to do all such

acts, deeds and things in the name of and on behalf of the society in relation to any of the matters aforesaid for the purposes of the society ;

(xii) to delegate all or any of the powers, authorities and discretions vested in him to an employee or employers of any society, subject to the ultimate control and authority being retained by him."

10. In section 34 of the principal Act, after sub-section (7) the following sub-section shall be inserted, namely :— Amendment of section 34.

"(7-A) Notwithstanding anything contained in this Act or in the bye-laws of a society—

(i) a Government servant may be nominated under this section by the State Government or by the authority specified under sub-section (7) either by name or by official designation ;

(ii) a Government servant so nominated by official designation may depute any other officer subordinate to him to attend any particular meeting of the Committee of Management, and such officer shall have the right to participate in the deliberations of the committee and shall also have the right to vote."

11. After section 35 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely :— Insertion of new section 35-A.

"35-A. (1) Without prejudice to other provisions of this Chapter, where for two successive co-operative years (including any period before the commencement of this section) :—

(a) more than seventy per cent of the total dues of any primary society, which is a credit society against its members during any co-operative year, remain unpaid at the end of such year ; or

(b) the number of defaulting members exceeds seventy per cent of the total number of indebted members of such society, at the end of any such year,

then, the Chairman and all members of the Committee of Management of any such society shall, upon an order coming into effect under sub-section (3), vacate their respective offices as such.

(2) The provisions of sub-section (1), as they apply to a primary credit society, shall *mutatis mutandis* apply to a financing bank with the substitution of references to 'seventy per cent' by references to 'sixty per cent'.

(3) In relation to any society or bank as referred to in sub-section (1) or sub-section (2), the Registrar may make such arrangements as he thinks proper for the management of the affairs of such society or bank, as he thinks fit and the provisions of sub-sections (3), (4), (5) and (6) of section 35 shall *mutatis mutandis* apply."

12. In section 44 of the principal Act in sub-section (2), in clause (b), the words and brackets "(hereinafter in this Chapter referred to as apex society)" shall be omitted. Amendment of section 44.

13. In section 45 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (b), the words and brackets "(hereinafter in this Chapter referred to as central society)" shall be omitted. Amendment of section 45.

14. In Chapter IX of the principal Act, after section 71, the following section shall be inserted, namely :— Insertion of new section 71-A.

"71-A. (1) If a co-operative society is unable to pay its debts (hereinafter in this section referred to as the debtor-society) by reason of its members defaulting in the payment of the moneys due to another Co-operative Society (hereinafter in this section referred to as the creditor-society), and the Committee of Management of the debtor-society omits or neglects to take necessary steps for recovery of money due from its members, the creditor-society may, notwithstanding anything in this Act, direct the said committee by a notice in writing to proceed against the defaulting

Powers of creditor society against debtor society and its members.

members in accordance with the provisions of section 70 or section 92, as the case may be.

(2) If the Committee of Management of the debtor-society fails to comply with the notice referred to in sub-section (1) within a period of thirty days from the date of service of such notice, the creditor-society may itself proceed against such defaulting members in accordance with the provisions of section 70 or section 92, as the case may be, as if they were members of the creditor-society, and in that event, the provisions of this Act and the rules made thereunder and the bye-laws of the debtor-society shall so apply as if all references to the debtor-society and its Committee of Management and officers in the said provisions were references to the creditor-society and its Committee of Management and officers.

(3) Where the creditor-society has in respect of any money due from the debtor-society, obtained an award or order referred to in section 92 against the debtor-society, the creditor-society may proceed to recover such money in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder, either from the assets of the debtor-society or from the members thereof to the extent of the debts due from them to the debtor-society, or from both."

Insertion of new section 95-A.

15. After section 95 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"95-A. (1) The registrar may, on an application made by a society referred to in section 34 or an agricultural credit society, for the recovery of arrears of any loan advanced by it or any instalment thereof to any member and on its furnishing a statement of accounts in respects of such loan and after making such inquiries, if any, as he thinks fit, issue a certificate for recovery of the amounts due.

Special provision for recovery of certain dues of agricultural society.

(2) A certificate issued by the Registrar under sub-section (1) shall be final and conclusive proof of the dues which shall be recoverable as arrears of land revenue."

Amendment of section 103.

16. In section 103 of the principal Act, in sub-section (2) —

(i) in clause (a), the brackets and figures "(vi)" shall be *omitted*;

(ii) for clause (b), the following clauses shall be *substituted*, namely:—

"(b) whoever commits an offence under clause (ii), clause (iii) or clause (vi) of sub-section (1) shall on conviction be liable to be punished with imprisonment of either description which may extend to two years and shall also be liable to fine which may extend to three thousand rupees;

(c) Every offence referred to in clause (b) shall be cognizable and bailable."

Insertion of new section 117-A.

17. After section 117 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"117-A. No expenditure from the funds of a society shall be incurred without prior sanction in writing of the Registrar for the purposes of defraying the costs of any proceedings filed or instituted in any court by any officer or Committee of Management of the society against any order made or purporting to be made by the Registrar or the State Government under section 29, section 34, section 35 or section 35-A".

Control of expenditure on litigation in certain cases.

Insertion of new section 122-A.

18. After section 122 of the principal Act the following section shall be inserted, namely:—

"122-A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may by rules provide for the creation of one or more services of such employees of such co-operative societies or class of co-operative societies as the State Government may think fit, common to such co-operative societies and prescribe the method of recruitment and conditions of service of persons appointed to any such service.

Centralization of certain services.

(2) When any such service is created, employees on the posts included in such service may, if found suitable, be absorbed in the service, provisionally or finally, unless any such employee by notice in writing in that behalf to the prescribed authority within the prescribed period intimates



his option of not becoming a member of such service and the services of others shall stand determined in the prescribed manner :

Provided that where an employee gives such notice as aforesaid, his services in the society shall stand determined with effect from the date of such notice and he shall be entitled to compensation from the society which shall be as follows :—

(a) in the case of permanent employee, a sum equivalent to his salary (including all allowances) for a period of three months or for the remaining period of his service, whichever is less ;

(b) in the case of a temporary employee, a sum equivalent to his salary (including all allowances) for a period of one month or for the remaining period of his service, whichever is less :

Provided further that where any such person holds a lien on any post other than post included in the said service, he shall be entitled to revert to the post on which he holds the lien and if he so reverts, he shall not be entitled to any compensation."

19. In section 125 of the principal Act,—

Amendment of section 125.

(a) in sub-section (2), the words "after affording another opportunity of being heard to the societies concerned" shall be omitted :

(b) in sub-section (4), for the words "three months from the receipt of the preliminary resolution referred to in sub-section (3), by all the members and creditors of all the societies", the words "thirty days from the date of receipt of the copy of the preliminary resolution under clause (a) of sub-section (2) of section 15 or, as the case may be, from the date of its publication in a newspaper under clause (b) of that sub-section" shall be substituted.

20. In section 126 of the principal Act—

Amendment of section 126.

(a) in sub-section (2), the words "after affording another opportunity of being heard to the Society concerned" shall be omitted ;

(b) in sub-section (4), for the words "three months from the receipt of preliminary resolution referred to in sub-section (3) by all the members and creditors of the society", the words "thirty days from the date of receipt of the copy of the preliminary resolution under clause (a) of sub-section (2) of section 15 or, as the case may be, from the date of its publication in a newspaper under clause (b) of that sub-section" shall be substituted.

21. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any contract or instrument, all sums deposited in the U. P. Co-operative Bank Limited (hereinafter referred to as the Bank) on behalf of the sugarcane growers of Uttar Pradesh in pursuance of the State Government notifications no. 3072-S-(2)/XII-C-188-1948, dated November 24, 1948 and no. 3321-S/XII-C-188-1948, dated January 19, 1949, by way of fixed deposits, including interest thereon, which remains unclaimed by the cane growers concerned, on the twenty-fourth day of November, 1975, shall be paid by the Bank to the Uttar Pradesh Ganna Kisan Sansthan Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (hereinafter referred to as the Sansthan) within such period as the State Government may, by general or special order direct.

Transfer of certain unclaimed deposits to the Sansthan.

(2) Any dispute between the Bank and the Sansthan about the amount to be transferred under sub-section (1) shall be decided by the State Government, and its decision shall be final and binding on both.

(3) The Sansthan shall keep the sums so received in a separate account and hold them in trust on behalf of the depositors or their legal representatives, as the case may be.

(4) The payment of the said sums by the Bank to the Sansthan shall discharge the Bank of the liability in respect thereof to the extent only of the amounts so paid and the liability to make that payment to the depositors or their legal representatives to the extent aforesaid shall stand transferred to the Sansthan.

(5) As soon as may be after the payment to the Sansthan under sub-section (1) the Sansthan shall publish, in such manner, a general notice, containing all such particulars, as the State Government may by order direct, inviting claims (to be preferred within a period of three months from the date of first publication of the notice) by the depositors or their legal representatives, as

the case may be, for any payment due to them out of the amounts so transferred to the Sansthan.

(6) Any claim received in pursuance of the general notice shall be decided by Cane Commissioner, Uttar Pradesh; or an officer not below the rank of Assistant Cane Commissioner nominated by him (hereinafter referred to as the Claims Authority).

(7) If a claim is rejected by the Claims Authority, under sub-section (6), the claimant shall have a right to appeal before the District Judge of the district in which the depositor was a member of a cane growers' co-operative society. The appeal shall lie within sixty days from the date of the order of the said authority.

(8) The decision of the Claims Authority under sub-section (6) shall, subject to the result of any appeal under sub-section (7), be final, and the decision of the District Judge in such appeal, if any, shall be final.

(9) Out of the amounts transferred to the Sansthan, any amount for which no claim has been made within the time specified in the general notice or in respect of which the claims filed as aforesaid have been finally rejected shall be deemed to be abandoned property and shall vest in the State as *bona vacantia* and shall be deemed to be transferred to and form part of a Fund to be called the Uttar Pradesh Ganna Vikas Fund.

(10) The Fund shall vest in and be held and administered by the Sansthan for the purposes of development, research and training in the cultivation of cane and such other purposes of common utility for the cane growers as the Cane Commissioner may from time to time direct.

Repeal and savings.

22. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Ordinance, 1976, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal or the repeal of the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1975, and the Uttar Pradesh Sugarcane Growers Deposits in the Uttar Pradesh Co-operative Bank Limited (Trust for Unclaimed Deposits) Ordinance, 1975 by the Ordinance mentioned in sub-section (1) anything done or any action taken :—

(a) under the principal Act, as amended by the said Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1975, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act :

Provided that when under sub-section (4) of section 29 of the principal Act as so amended, an *ad hoc* committee was appointed by the Registrar for the administration of any society, he shall, not later than two weeks from the commencement of this Act, appoint an Administrator in place of the *ad hoc* committee, and until an Administrator is so appointed, the *ad hoc* committee shall be in charge of only the current duties of the Committee of Management :

"Provided further that in respect of a society other than an apex or a central society where the Registrar has appointed an Administrator, he may, if he thinks fit, restore the management of the society to the outgoing Committee of Management, without prejudice to his powers to act again under the said sub-section (4) whenever he so thinks fit ; or"

(b) under the Uttar Pradesh Sugarcane Growers Deposits in the Uttar Pradesh Co-operative Bank Limited (Trust for Unclaimed Deposits) Ordinance, 1975, shall be deemed to have been done or taken under section 22 of this Act.—

as if this Act were in force at all material times.

आज्ञा से

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव

U. P. Ordinance no. 3 of 1976.

U. P. Ordinance no. 26 of 1975.

U. P. Ordinance no. 36 of 1975.

U. P. Ordinance no. 31 of 1975.